Title: Need to clear the proposal of Government of Bihar for setting up of a Leechi Consortium.

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : सभापति जी, फलों की रानी "लीची" फल कुल राट्रीय उत्पादन का 80 प्रतिशत अपने बिहार राज्य में होता है। मगर समुचित ख़रखाव, आधुनिक तकनीक एवं आधारभूत संसाधनों की कमी के कारण लगभग 70 हजार टन फल प्रतिर्वा बर्बाद हो जाता है। केवल यूरोप में लीची फल की मांग 30 हजार टन है। मगर बिहार से 50 टन भी निर्यात नहीं हो पाता है। जबकि मडागास्कर अपने उत्पादन का 80 प्रतिशत एवं इजराइल 90 प्रतिशत लीची निर्यात कर भारी विदेशी मुद्रा कमाता है। उत्पादन प्रौद्योगिकी, परिरक्षण, प्रसंस्करण उद्योग, भण्डारण एवं परिवहन की सुविधा के अभाव में देश के बाकि शहरों में ताजी लीची पहुंचाना संभव नहीं हो पाता। केन्द्र सरकार मशाला बोर्ड, टी बोर्ड, काफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, नारियल बोर्ड बनाकर दूसरे राज्यों के किसानों को उनके गुणवत्तापूर्ण उत्पादन से लेकर उसके विपणन तक में सहायता कर रही है। मगर बिहार के इस फल को केन्द्र सरकार द्वारा महत्व प्रदान नहीं किया जा सका है। जबकि बिहार राज्य निर्यात निगम, पटना द्वारा " लीची कन्सोर्टियम " बनाने का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है।

अतः केन्द्र सरकार के कृषि एवं वाणिज्य मंत्रालय से मांग करता हूं कि शीघ्र " लीची कन्सोर्टियम" बनाया जाए।